workers at the rate of 4% of their wages with effect from the accounting year 1965-66.

The Government have now decided to advise the Major Port authorities to calculate the advance payable to the port workers on the basis of the "Khadilkar Formula", as an interim measure, pending further consideration of the Bonus issue by the Government. These calculations would be made for the accounting year 1970-71. The question whether the payment should be made immediately or later would be decided soon.

†RELIEF TO AGED AND DESTITUTE

367. SHRI A. D. MANI: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE/शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री be pleased to state whether it is under consideration of Union Government to give a monthly pension of Rs. 20/- to aged persons who are utterly destitute in the union territories as a gesture of relief to the aged and destitute ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE/शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (SHRI K S. RAMASWAMY): No such proposal is under consideration now

—

12 NOON

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ARMED ATTACK BY LANDLORDS ON SANTHALS IN PURNEA DISTRICT, BIHAR RESULTING IN DEATH OF 14 SANTHALS AND INJURIES TO SEVERAL OTHERS

SHRI NIRANAJAN VARMA (Madhya Pradesh): Sir, I beg to call the attention of Minister of Home Affairs to the recent armed attack by landlords on Santhals in Purnea District, Bihar, resulting in the death of 14 Santhals and injuries to several others.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS गृह मंत्रालय में उपमंत्री (SHRI F. H. MOHSIN): Mr. Chairman, Sir, on the 22nd November, ghastly and tragic incidents occurred in village Rupaspur, Police Station Dhamdaha, District Purnea in Bihar. Information so far available with the State Government indicates that a plot of land had been cultivated by one Kandan Murnu of Santhal Tola. At about 3 30 p. m. on 22nd November, a mob of about 150 armed with bows, arrows, bhala, garasa, etc. came to the plot and began cutting unripe paddy. Some of them were keeping guard. When a few Santhals who lived close by approached the plot in dispute, they were chased away by the mob. The mob then came over to the Santhal Tola and was joined by another mob armed with guns and accompanied by tractors, trailers and station wagon. The two mobs surrounded the Santhal Tola, locked the houses from outside and set fire to them In all 45 houses were burnt. Those who tried to escape were shot at. Injuries were also inflicted by garasas and other weapons Some of the dead bodies of those who were killed were whisked away in tractors So far four bodies have been recovered from houses and ten from the Kosi river bed. Reports have so far been received about injuries to 33 who are stated to be receiving medical treatment. Criminal case has been registered and 12 persons have so far been arrested. In the FIR lodged by the Santhals, 29 persons have been named as accused. Warrants and processes under Criminal Procedure Code have been taken out against absconding accused and investigations are in progress The Chief Minister, Bihar, visited the village, on receipt of information regarding these incidents.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR]

Senior police officers are camping in the area and necessary measures have been taken to maintain peace and prevent any recrudescence of trouble. The Deputy Superintendent of Police and the Block Development Officer concerned have been suspended for negligence. A sum of Rs. 3000 has been distributed as immediate relief to the affected villagers. The State Government is examining the question of grant of further

†Transferred from the 19th November, 1971.

[Shri F. H. Mohsin]

elief to the affected villagers A proposal in this regard has been received through the Commissioner, Bhagalpur, and is under consideration of the Government. The Government of India are keeping in close touch with the State Government and will provide whatever assistance that may be required by the Government of Bihar in taking action according to law against the persons responsible for the commission of these heinous offences

श्री निरंजन वर्मा श्रीमन् माननीय मन्त्री जी ने अभी केवल उस वक्तव्य को पढ दिया जो लोक सभा में दिया गया था। इसमे तो कोई और अधिक जानकारी नही दी गई। तो मैं उनसे यह जानना चाहता हू कि पहली बात तो यह बताइए कि इसमे कितने आदमी वास्तव मे मरे हैं क्योंकि आपने तो 4 आदमी बताए हैं जब कि वहा के लोगों का ऐसा खयाल है कि कम से कम 15 आदमी मरे हैं। दूसरी बात आप यह बताइए कि जो पहला मौब एटेक करने वालो का था वह क्या सथाल जाति के लोगो का था या कोई दूसरे लोगों का था। तीसरी बात यह कि उनके साथ फिर एक दूसरा मौब 150 आदमियों का मिल गया जिनके साथ मे ट्रैक्टर थे, स्टेशन वैगन थे और तरह तरह के हथियार थे, तो उन लोगों के पास जितने भी वाहन थे, वे वाहन अभी तक जब्त किए या नही या उन लोगो के हथियारो को जब्त किया या नही किया? 150 आदमियो का जो मौब आया, जिनके साथ मे दूसरे लोग मिल गए थे, क्या ये लोग किसी एक विशेष राजनैतिक विचार-धारा के व्यक्ति थे जिसके कारण उनको अभी तक छुवा नही गया है और कई एक आदमियो को छोड दिया गया है। आप यह भी बताए कि आपने बताया कि एफ० आई० आर० दर्ज कर दिया गया है। तो एफ० आई० आर० दर्ज करते समय क्या आपने धारा 402, 149 379 इत्यादि लगाई कि नही, इनके अतर्गत उन सभी व्यक्तियो को वहा पर गिरफ्तार करके लाया गया या नही, या वे एब्सकाड कर रहे है इसलिए छोड दिया गया? इसके बाद यह बताइए कि ये 3,000 रु० जो आपने वहा पर दिए हैं, तो इसमे उन लोगो के लिए जिनके मकान जलाए गए है, उनके रहने के लिए, आश्रय के लिए, भी आपने कुछ किया या नहीं किया और उनको टेम्पररी ड्वेलिंग्ज के लिए क्या आपने किसी प्रकार की कार्यवाही कि है या नही? इन सब बातो का उत्तर देने का मत्री महोदय कष्ट करे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) उपसभापति महोदय, जो लोक सभा में मैंने वक्तव्य दिया था और जो आज दिया है, उसमे थोडा सा अतर है

श्री निरंजन वर्मा एफ० आई० आर० का है।

श्री के० सी० पन्त: आप दोनों पढ लिजिएगा, आप भी समझ लेंगे क्या अतर है और वह अतर उतना ही है जितना कि कुछ और हमको सूचना मिली है। मसलन, उसमे जितने लोग पकडे जाने की सूचना है, इसमे ज्यादा नही पकड़े गए। उसमे यह बात दी गई है कि राज्य सरकार सोच रही है कि 3,000 रु० से ज्यादा सहायता पर विचार करेगे। दो चीजे इसमे और दी गई है।

अब कितने लोग मारे गए, इसकी सूचना आपने पूछी। 14 आदमियों की खबर हमारे पास है और अभी वह सूचना सदन को दी गई। और भी कई प्रश्न आपने पुछे है। अध्यक्ष जी, इसमे वर्मा जी ने बारबार पूछा कि इसमे आपने कौन सी दफाए लगाई आपने क्या सहायता की, तो मैं शुरू मे ही यह निवेदन करना चाहता हू कि यह ला एन्ड आर्डर का मामला राज्य सरकार का मामला है, क्या सहायता उनको देनी चाहिए, यह राज्य सरकार का मामला है। जिस तरह से इसकी तहकीकात की जाए, वगैरह, यह राज्य सरकार

का मामला है। यह सही है कि यह एक ऐसा काड, ऐसी घटना हुई जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और जिसको हम बहुत बुरा समझते हैं इसलिए यहा उसकी चर्चा हो इसमें कोई नुकसान नही है। इससे अगर ऐसे जो हादशात होते हैं, उस पर कुछ रोशनी पडे और सब जगह लोगों के मन में यह भावना जाग्रत हो कि इस तरह की चीज नही होनी चाहिए देश मे, तो ससद मे चर्चा होनी चाहिए लेकिन जो दायरा राज्य सरकार का है उसमें और केन्द्र सरकार मे कुछ अतर है ही, वह अतर रहेगा।

अब ये जो मामले आपने पूछे कि वे सथाल थे या नही, कुछ हथियार जब्त हुए या नही हुए, तो ये सारी चीजें वहा जो इन्क्वायरी हो रही है राज्य सरकार की तरफ से उससे मालूम होगा। दफाएं क्या क्या थी, उसकी सूचना मेरे पास है। अब इसमे कुछ अतर हुआ, लोक सभा में जब मैंने वक्तव्य दिया था उस समय मेरे पास जो सूचना थी उसमे। वह इस प्रकार है——

> A police case dated 23-11-1971 under sections 147,148,149,436,379, 364, 201 and 34, I. P. C. read with section 27 of the Arms Act has been registered.

कुछ विशेष राजनैतिक विचारधारा की वजह से कुछ लोगों को नही पकडा, यह आपने कहा। मैं इस के बारे में नही जानता हू, लेकिन जितने लोग पकडे गये हैं, उसकी सूचना मैने दे दी है। पहिले सूचना हमारे पास यह थी कि 6 लोग पकडे गये हैं, 6 के बाद फिर 10 हो गई और अब 12 हो गई है। अब तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार 12 लोग पकडे गये हैं।

श्री निरंजन वर्मा : मैं मत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हू और उनसे यह जानना चाहता हू कि यह बात सही है कि जहा तक ला एन्ड आर्डर का प्रश्न है यह राज्य सरकार का है, और वह इस बारे में जाच पडताल कर रही है। तब भी यह एक ऐसा मामला है जिस पर भारत सरकार को कुछ थोडा बहुत पता चलना चाहिये था और उनके जरिये हम भी इस बारे मे जानना चाहते थे। आपके पास साधन है और आप मोटे तौर पर इस मामले के बारे मे तलाश कर सकते थे। तो मैं यह जानना चाहता हू कि जो 150 आदमी थे वे किस विचारधारा के थे और किस पार्टी के थे ? यह तो मुमकिन था कि जो ट्रेक्टर लाया गया था वह तो धारा 302 के अन्तर्गत तत्काल जब्त किया जा सकता था। सब से बडी बात यह है कि आपने इस बारे मे तलाश नही किया। 19 एफ और 27 धारा जो लगाई गई है वह तो आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत एक माइनर आफेन्स है, लेकिन 302 के अन्तर्गत जो सब से अधिक और भयानक आरोप है उसे लगाया गया या नही लगाया गया ? यह बात तो आप वायरलैस से पूछ सकते थे।

श्री के० सी० पन्त : मैंने बतलाया कि जो मेरे पास सूचना थी वह मैंने आपके सामने रख दी है और इसमे कुछ छिपाया नही है। अगर इसमे राय काफी नही है और ज्यादा सूचना चाहते हैं, तो मैं बिहार सरकार को कह सकता हू।

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, the very statement that has been made by the hon. Minister in the Lok Sabha and also here depicts the heinous crime that has been committed by a section of the landlords in that village on the Santhals there I am clear in my mind that the Government of Bihar has failed to give adequate protection to the weaker sections of the community, particularly those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as envisaged in article 46 of the Constitution. Sir, in the course of his reply the hon Minister has referred to the question of jurisdiction of the State Government with regard to law and order. But the jurisdiction of the Central Government is also there because under article 46 of the Constitution, the entire country, the entire Parliament

[Shri Chitta Basu]

particularly the Government of India, is committed to creating the necessary conditions for the protection of the rights of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also protect them from exploitation May I know whether the Government of India is conscious of this responsibility? If they are conscious of this Constitutional obligation, what steps does the Government propose to take in the matter, to give a direction to the Government of Bihar in the matter of providing much more security, much more protection, for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes there ?

My second point is, the statement reveals that it was an organised attack on behalf of certain jotedars and zamindars on the Santhals That it was an organised attack is proved by the facts given in the statement itself A mob was there, its number was about 150 Tney were carrying arms They entered the plot of land and started cutting the unripe paddy It is said in the statement that another mob joined them and they were accompanied by a station wagon and some tractors and trailers and tney had also guns in their possession Both these mobs locked the Santhals in their houses and set fire to the houses and anybody who tried to escape was shot at point-blank Sir, all these things could not have been done unless there was a conspiracy How could the station wagon be mobilised ? How could the guns be mobilised ? How could the trailers and tractors be mobilised ? How could 3000 people be mobilised ? And all the while the local police station was quite ignorant about the whole thing Sir, this means that there was a premeditated attack on the Santhals, May I know from the honourable Minister, whose station-wagon it was, whose guns they were, whose tractors they were, whose trailers they were, and whether the owners of the tractors, the owners of the trailers, the owner of the station-wagon, the owners of the guns, have been arrested and whether the guns have been seized ? In this connection may I know from the honourable Minister whether it is also not a fact tnat in Bihar the jotedars and zamindars have got a large number of guns at their disposal and they very much use these guns during the time of harvesting in order to terrorise the bagadars and sharecroppers and other poor tenants in the region ? May I know whether tne Government of India proposes to seize all the guns now in the hands of these jotedars and zamindars so tnat this kind of attacks cannot be repeated in otner parts of Bihar ? Will the Government of India advise the Government of Bihar to take such action ? May I further know why the Government does not agree to send a team of Members of Parliament to go there to inquire into the whole matter and submit a report to the House so that the necessary climate could be created in the country that Parliament is really seized of the matter and tnat it will try to protect the interests of the weaker sections of tne community, that Parliament is discharging its responsibility in the matter of providing protection and guarantee ? Why does not the Government consider it advisable and necessary to send a Parliamentary Committee for the fulfilment of the said objective ?

SHRI K C PANT : We have already said in our statement that this is ghastly and tragic incident and it is a heinous crime as my honourable friend Shri Chitta Basu, says

SHRI CHITTA BASU : Most heinous

SHRI K C PANT : Most heinous if you like

SHRI A D MANI (Madhya Pradesh) : Gruesome

SHRI K. C PANT : Certainly, shocking is a milder term.

He says that the Government of Bihar has failed to give protection to the weaker sections and he has made a general reference to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes We are proud of the fact that the Chief Minister of Bihar happens to be a person who belongs to what is generally known as weaker sections .

SHRI CHITTA BASU : But that is no guarantee.

SHRI K C PANT : . . . and I am quite certain in my own mind that he would be doing his best, I am quite cer-

tain that his motives in this respect cannot be doubted. So, althogh thin incident is very regrettable and we are very, very, concerned by it, I do not think we should take a position that seems to put the motives of the Bihar Government in doubt . . .

SHRI CHITTA BASU : It is a fact that they have not provided the guarantee.

SHRI K. C. PANT : Then, he wants us to issue directions. I hope that in other cases also it will be his view that the Centre should issue directions to the State Governments. If that is his general approach to the problem, I will consider his suggestion.

SHRI CHITTA BASU : But this is a particular problem. You have got a constitutional obligation to provide protection and guarantee against exploitation of this kind.

SHRI K.C. PANT : That is all right. If it is your general proposition, I will consider your suggestion. I have already said that we are keeping close touch with the State Government and will provide whatever assistance may be required by the Government of Binar in taking action, according to law, against persons who are responsible for the commission of these heinous offences. That we have already said in our statement. Regarding premeditated nature of the attack and so on, all these are matters of inquiry. Obviously it has the appearance of a premeditated attack. But I would not like to comment on any thing that is being investigated or inquired into. So far as seizing the guns goes, that is a matter for the Bihar Government to consider. . .

SHRI CHITTA BASU : But you can advise.

SHRI K. C. PANT : But you see Bihar the situation is a complicated and complex one. There are incidents in which guns may be needed for protection. There are anti-social elements also in Bihar who are sometimes going on a rampage in the rural areas. So this as a matter which can only be decided by the State Government after taking into consideration the entire situation at a particular locality or a particular spot.

Regarding the Committee of Parliament, I do not really know what such a committee can do in the matter when investigation is going on. The State government is obviously very much concerned by the incident so much so the Chief Minister has himself visited the spot and senior officers are camping there. The Chief Minister's visit underlines the importance the Government of Bihar is attaching to this incident. I would request the hon. Member to consider whether we should take any step which may give an impression that the Government of Bihar is not doing its utmost in this matter.

SHRI CHITTA BASU : Has the owner of the Station Wagon or the tractor and trailor been arrested ?

SHRI K. C. PANT : That was asked by Shri Niranjan Varma. I do not have those details.

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : पूर्णिया जिले के रुपसपुर गांव में जो घटना हुई है उस का मैंने घटनास्थल पर जा कर निरीक्षण किया है और वहां जो कुछ भी देखा उसे देख कर ऐसा लगता है कि वहां जलियांवाला बाग की घटना की पुनरावृत्ति हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। मंत्री महोदय ने जो भी बयान दिया है उस के बाद भी इस बात की सफाई नहीं हुई कि वहां 45 घर संथालों के जो सर्वे के कब्जे से बसे हुए थे और जिन का 60 बीघे जमीन पर शिकमी अधिकार है और वहां यह घटना हुई है 22 तारीख को, उस के केवल 15 दिन पहले एस० डी० ओ० ने वहां जा कर संथालों और जमींदार परिवार के बीच समझौता करा दिया था। वह जमींदार परिवार एक पुराना प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेता परिवार है श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु का परिवार है। वहां एस० डी० ओ० ने जा कर जमींदार परिवार और उन संथालों के बीच यह समझौता कराया कि यह संथालों की जो

[श्री भोला प्रसाद]

शिकमी जमीन है, उस जमीन पर जो फसल संथालों ने बोयी है उसको कानून के मुताबिक संथालों को काटने का हक है और संथाल उस फसल को काट कर 30/10 के हिसाब से बंटवारा करेंगे, यानी मन में 30 सेर बटाईदार लेंगे और 10 सेर मासिक को देंगे। यह समझौता एस० डी० ओ० ने 15 दिन पहले वहा कराया इसलिए संथाल निश्चिन्त थे यह सोच कर कि एस० डी० ओ० साहब ने आ कर खुद यह समझौता करा दिया है और जमींदार ने उस समझौते को माना है, तब फिर कोई आशंका नहीं हो सकती कि उनकी फसल लूटी जायगी, उनके गांव पर या उनके स्थान पर इतना बर्बर हमला होगा, इस की उनको शंका नहीं थी और इसलिए जिस वक्त हमला हुआ तो यह संथाल, वहा के गरीब किसान सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हमला हो सकता है। सरकार को यह बताना चाहिए कि जो डी० एस० पी० सस्पेंड किया गया है उस के चार्ज में वहां एक पुलिस का दस्ता बिठाया गया था जिस में कि जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक फसल का बंटवारा ठीक से हो और फिर कोई झगड़ा झंझट वहां न हो लेकिन उस डी० एस० पी० ने जिस का नाम शिवपालक सिंह उर्फ लाठी सिंह है . . . .

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : आप ने कहा कि कांग्रेसी नेता का परिवार है। कांग्रेस आर० वाले हैं या कांगो वाले, यह भी बता दीजिए।

श्री भोला प्रसाद : अभी वह दोनों के बीच में डोल रहे हैं। कांगो और कांग्रेस (आर०) के बीच में।

श्री उपसभापति : आप अपना सवाल पूछ लिजिए, भोला प्रसाद जी।

श्री भोला प्रसाद : उपसभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि डी० एस० पी० ने दो दिन कब्ल वहां से पुलिस पोस्टिंग को हटा दिया, जिस दिन 22 तारीख को यह घटना हुई उसके दो दिन कब्ल वहां से पुलिस को हटा दिया और यह इस बात का सबूत है कि डी० एस० पी० और जमींदार परिवार के लोग साथ थे और खुद डी० एस० पी० जमींदार परिवार का कुछ रिश्तेदार ही माना जाता है और यह भी सुना जाता है कि सब जमींदारों ने मिल कर के डी० एस० पी० को 50 बीघा जमीन देने का वचन दिया है। उस डी० एस० पी० ने पुलिस को दो दिन कब्ल हटा दिया और डी० एस० पी० ने और तमाम जमींदार परिवार वालों ने मिल कर यह योजना बनाई कि जो 22 तारीख को यह यकायक घटना हुई।

(Time bell rings)

SHRI CHITTA BASU : Yes. Sir, He has visited the place.

श्री भोला प्रसाद : उपसभापति महोदय, इतना ही नहीं, उस घटना के बाद श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु के लड़के श्रीप्रद्युमन नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया और एफ० आई० आर० में उसका भी नाम है। जहां पर इतने मर्डर हुये हैं, इतनी नृशंस हत्यायें हुई हैं, इनके गांवों को जलाया गया है उस केस में प्रद्युम्न नारायण सिंह जो कि श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु के लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद खुद दरोगा ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। क्या कानून में ऐसा कोई उदाहरण मिल सकता है कि जो इतने बड़े जुर्म में मुजरिम हो उसको खुद दरोगा ने जमानत पर छोड़ दिया हो। उनको छोड़ दिया और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री उपसभापति : सवाल पूछिये।

SHRI CHITTA BASU : Sir, this is the question.

श्री भोला प्रसाद : मैंने खुद यह सवाल वहां किया था।

श्री निरंजन वर्मा : मंत्री जी ने इन बातों का उत्तर नहीं दिया है।

श्री भोला प्रसाद : उपसभापति महोदय, मैंने एस० पी० के सामने लिख कर यह सवाल उसी दिन 27 तारीख को पेश किया था। इसके बाद में सरकार को यह भी बताना चाहता हूं और सरकार से जानना चाहता हूं कि वहां जो 22 तारीख का हमला हुआ उसमें न केवल वहां के जमींदार परिवार के लठैत थे, उनकी बन्दूकें और तमाम चीजे थीं बल्कि जितने भी गोहारे आये थे उसमें पूर्णिया इलाके के बड़े बड़े जमीदारों के लठैत थे। मौलिचन्द्र जिसके पास 20 हजार एकड़ जमीन है वह पूर्णिया इलाके के, भागलपुर के जमीदार है उनके लिठैत थे और रामगुलाम साहू जिसके पास 25 हजार एकड़ जमीन है उसके भी लठैत आये थे, उनकी बन्दूकें आई थीं, दो दर्जन बन्दूके थीं और इन तमाम लोगों ने कांसप्रेसी कर के, योजना बना कर के जिसमें कि पुलिस का हाथ था यह बर्बर हमला, इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने किया।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिय आपने काफी जानकारी दे दी है।

SHRI CHITTA BASU : He want to know whether this is correct or not.

श्री उपसभापति : उनके पास में जानकारी है तो वह बैठे, उनको सवाल पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री भोला प्रसाद : उपसभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के बाद खुद सरकार ने क्या कार्यवाही की है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, पूर्णिया जिले के कांग्रेस कमेटी के एक गांव का बयान आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वह खुद कांग्रेस (आर०) के है।

श्री उपसभापति : आपको समय नहीं है। स्टेटमेंट मत पढ़िये। 10 मिनटे आपको हो गये। संक्षिप्त में कहिए, जो कुछ कहना है।

श्री भोला प्रसाद : खुद पूर्णिया जिले के कांग्रेस कमेटी के मंत्री ने कहा है।

श्री चित्त बासु : उनको जानकारी है। यह जानकारी सरकार को है या नहीं, यह उनका सवाल है।

श्री भोला प्रसाद : उन्होंने इस घटना के बारे में बड़े जोरदार तरीके से गवर्नमेंट से कहा है कि इसमें पुलिस और जमींदार का मिला हुआ हाथ है और उन्होंने मिल कर किया है और यह सरकार के लिये बहुत ही शर्मनाक बात है।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप बैठिए

श्री भोला प्रसाद : उपसभापति महोदय, उसके बाद भी वहां घटनायें हुई है। इस घटना के बाद 29 तारीख को वहां पर बगल में कसबा गांव में पांच सौ जमींदारों के लैठतों ने मिल कर के हमला किया है। 20 बीघा जमीन वहां पर बटाईदारों ने बोई थी और जमीदार थे वहा के हसीबुर रहमान जो कि किसी वक्त शोशलिस्ट पार्टी के नेता और मिनिस्टर थे और अभी वह कांग्रेस (आर०) में गये हैं, उनके हथियार बन्द गुन्डों ने वह हमला किया और वहा पर फसल लूटी और पूर्णिया जिले के कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री मोहन शर्मा को बूरी तरह से घायल किया है। और वह अभी अस्पताल में पड़ हुय हैं। उसके बाद भी ये घटनाये हो रही है।

श्री उपसभापति : ठीक है, बैठिए प्लीज।

श्री भोला प्रसाद : महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की दर्जनों घटनाएं बिहार में हुई है।

और जिसके बारे में कम्युनिस्ट पार्टी ने बार बार वहा की सरकार को, मुख्य मंत्री को, चेतावनी दी है, याद दियायी है। इसलिये हम इस सरकार का समर्थन नही कर सकते है अगर यह सरकार जमींदारों के पक्ष

[श्री भोला प्रसाद]

में इस तरह से मिलकर ऐसी कार्यवाही करती है। आज वहां लोगों का विचार है कि भोला शास्त्री, जो कि एक हरिजन हैं, वह वहां के मख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में आज वहां की सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य से वह जमींदारों के दोस्त हैं, जमींदारों के हाथ में खेल रहे हैं।

श्री उपसभापति : भोला प्रसाद जी आप बैठ जाइए।

श्री भोला प्रसाद : उनके रहते किसानों के जान माल की और गांव की हिफाज़त नहीं हो सकती है।

श्री के० सी० पन्त : उपसभापति. जी यह पार्टी का सवाल नहीं है। अगर माननीय सदस्य 20 हजार या 25 हजार एकड़ के कृषकों की ओर ध्यान दिलाया चाहते हैं सदन का, तो मैं उनको याद दिलाऊंगा कि शायद कोई पार्टी बची हो जो बिहार में किसी न किसी वक्त सरकार में न बैठी हो और जिस वक्त आप वहां बैठे थे उस वक्त कोई कदम उठाते तो शायद वे बीस, पच्चीस हज़ार एकड़ वाले नहीं रहते। हम आज़ कदम उठा रहे हैं, उठाना चाहते हैं। और जहां तक भूमिसुधार का प्रश्न है, आपसे जादा उठा रहे हैं। इसलिए ऐसे मामले में पार्टी का सवाल नहीं उठता। यह बड़ा खौफनाक हादशा हुआ जिसके बारे में बहुत दर्द है सबको और हम ो देखना है कि इसमें जो भी मजरिम हो, चा वह कोई हो, उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको दंड दिया जाए। इसमें, जैसा मैंने आपसे कहा, केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार जो भी सहायता मांगेंगी हम देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Goray.

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra) Sir, I think that tnere will be no two opinions in this House regarding the heinousness of the crime that was committed in Bihar only a few days ago. Sir, in this regard I would like to make two or three observations.

One is that this is a *prime facie* case of conspiracy pre-meditated and pre-planned conspiracy. Sir, I would like to point out that there if another fact that only four bodies were recovered from the house and ten bodies were recovered from River Kosi bed, which is 33 kilo metres away from the scene of the ghastly tragedy. It is ample proof that after burning they tried to completely cover up the whole thing and, therefore, as many bodies as they could lay their hands on were collected, put into a truck and removed to a place 25 miles away from the scene of the tragedy. It was only becauss the Kosi river was perhaps merciful that these bodies came up and they were discovered, they were found the next day or the day after the next.

Sir, I am happy to know that the Chief Minister of Bihar visited the place. Here I may point out that even before that, the former Chief Minister, Mr. Karpuri Thakur, and the former Minister of Home Affairs, Shri Ramanand Tiwari, both visited that place, and Shri Karpuri Thakur made a detailed statement. . .

AN HON. MEMBER : A scathing statement.

SHRI N. G. GORAY : ....On this particular incident.

Sir, the other point I wanted to make was that again and again when such tragedies have taken place, it has been stated in this House that this is a question that comes within the jurisdiction of the State Government. Sir, I would like to say to the Home Minister that while they are contemplating certain progressive steps, this tension between the haves and have-nots is going to mount. But it may not only be in Bihar but in other places also that such tragedies may take place. Sir, It may be sometimes against the Santhals, sometimes against other Adivasis and some times against

Harijans. And right from Madras we have come across cases where Harijans have been done to death. How it is the Santhals. Therefore, I would ask the Minister whether he does not think it necessary to depute one of his officers to the spot, because, Sir, this is something connected with the welfare of scheduled castes and scheduled tribes.

And this House has again and again discussed the difficulties in which they live. We have a separate Commissioner for them. I would like to know from the Minister whether it will not be proper that he deputes some of his high police officers and carries on an independent inquiry. I would go one step ahead and say, if we are really serious to put into effect all the social legislation,...

SHRI CHITTA BASU : A separate legislation.

SHRI N. G. GORAY: ...I would even go further and say that let there be a separate enactment or legislation empowering the Central Government to act independently of the State Governments in such cases. Because, Sir, I do not care whether those men belong to the Congress or belong to the former PSP or the former SSP. I do not want to bring up their party affiliations here; it is immaterial. I would like to say this that it is very natural that if those people are powerful people there—the landlords—whichever party they may belong to, it will not be possible for the local police to go against them. Therefore, only an independent police inquiry by an independent police officer deputed from the Centre is likely to carry out an impartial investigation. Therefore, I would like to suggest to the Home Minister that they should depute an officer like that, and in order to anticipate further developments like this from the rest of India, they should think of a legislation also.

SHRI K. C. PANT : Sir, the framework within which Shri Goray has set his question is very thought-provoking, and it is certainly a question that needs deeper consideration. I can tell him the present position. We can make intelligence inquiries. Of course this is open to us in any State. But this cannot be investigation. They are merely intellegence inquiries and no more than that. If we want to carry on investigations through the CBI then, under the present dispensation, either the State Government must ask for such an inquiry, or must concur in such an inquiry. The reasons for that are obvious. I need not go into them. But this is the present position and, therefore, we cannot start an investigation in any State if the State Government is not willing to have it or has not asked for it. He suggested that we might depute a police officer to the spot to conduct an independent investigation. But this is subject to the present dispensation. One can of course ask the State Government if they would like the assistance of the CBI. Then, we would certainly render as much assistance as we can. If the State Governments want some one from the Social Welfare Department to go there, then I can take it up with the Education Ministry. But this is the present position. To his suggestion that there should be an enactment which would enable the Centre to investigate into such incidents independently, I would not like to give an off-the-cuff reaction as it is a larger question involving Centre-State relations, and the States would also have to consider it. But he has made the suggestion, and I would suggest that he also take it up with other parties and let us now their reaction. We would not like to initiate a suggestion of this kind at this stage for obvious reasons.

श्री गणेशी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश) : आज पूर्णिया जिले के संथालों का मामला लेकर इस हाउस में चर्चा चल रही है। मेरे लिए यह कोई नई बात नही है और देश में इस तरह की घटनाएं रोज छुटपुट रूप में सैकड़ों की तादाद में होती रहती हैं जिनका कही न रिकार्ड रहता है, न जिनके बारे में जानकारी हाउस की ही होती है न जिला अधिकारियों की ही होती है और न ही सूबे की गवर्नमेंट इस बात को जान पाती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आखिर यह छुटपुट रोज जो हरिजनों और गिरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? आज जो

[श्री गणेशी लाल चौधरी]

हरिजन हैं, गिरिजन हैं वे कर्ज से लदे हुए हैं ।

चार चार जनरेशन्स से एक-एक आदमी एक-एक महाजन के यहां काम कर रहा है और इतने दिनों काम करने के बाद भी जो हरिजन हैं, वह स्लेव्ज हैं, वे उनको छोड़ कर कहीं जा नहीं सकते ।

श्री उपसभापति : आप संथालों के बारे में बोलिए ।

श्री गणेशी लाल चौधरी : श्रीमन्, मैं संथालो के बारे में ही कह रहा हूं । संथाल भी ऐसे हैं जो कि कर्जे से लदे हुए हैं और चार-चार पीढियों तक उनके लड़के बच्चे जमीदारों के यहां हल जोत रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको छुटकारा मिल नहीं पा रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड़ है वह बहुत पुराना बना हुआ है और वह बहुत डिफेक्टिव है । जो आदमी चार पुस्तों से हल जोत रहा है और अगर किसी ने उसको कभी दस रुपया दे दिया होगा तो अब भी उसके ऊपर दो-दो चार-चार हज़ार रुपया बाकी है और उसका प्रोनोट अभी भी चला आ रहा है ; लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड के अन्दर हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं । जहां तक एविडेंस ऐक्ट का सवाल है, हम मारे जाते हैं, उसके बाद भी हमको गांव में कोई गवाह नहीं मिलता है । जो ऐक्ट हैं उनके द्वारा आज हमारा शोषण होता है । जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया आपके जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी है, उनसे मिल कर उच्च तब्के के जो लोग हैं वे हरिजनों को कत्ल करते हैं । जब हमारे उपर कोई घटना होती है तो थाने में जा कर उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है और हम उनको दंडित नहीं करवा पाते है । तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करवायेंगे कि आप का जो एविडेंस एक्ट है, आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है, आप का जो क्रिमिनल प्रौसिजर कोड है, इनमें आप ऐसे संशोधन करने का यत्न करेंगे जिससे हरिजनों को न्याय मिल सके ।

श्री के० सी० पन्त : उपसभापति जी, माननीय सदस्य की भावनाओं के लिये मेरे मन में आदर है और जिन तकलीफों को देख कर के इनके मन में ये विचार उठे है उनको भी मैं जानता हूं, लेकिन जो वास्तविकताएं है हमारे देश में उनको पहचान कर उनको दूर किया जा सकता है । आज भी बावजूद हर कोशिश के ऐसी सूरत अक्सर देखने में आती है जिस में हरिजनों को या जन जातियो को जो अधिकार कानून ने दिये हैं वास्तविकता में दैनिक जीवन में उनको प्राप्त नहीं होते । यही मैं कह सकता हूं कि हम सब को प्रयास करते रहना है, हर कोशिश करते रहना है कि वास्तविकता में वह सारा फायदा जो कि यह सदन-संसद और देश के नेता पहुंचाना चाहते हैं पिछड़े हुये वर्गों को वह उनको वाकई पहुंचा सके । इस में कभी-कभी दृष्टिकोण का सवाल आता है, कभी-कभी जो सरकारी मशीनरी है उसके दृष्टिकोण का सवाल आता है, कभी-कभी साधनो का प्रश्न आता है । इन सब पर गहराई से विचार करके काम किया जाता है तभी इस का कोई फैसला हो सकता है । आम तौर पर समाज में कुछ तो नजरिया बदला है पिछले वर्षों में, लेकिन हर जगह उतना नजरिया भी नहीं बदला जितना कि हम देखना चाहते हैं । जहां तक सिविल प्रोसिजर कोड, एवीडेंस ऐक्ट और क्रिमीनल प्रोसीजर कोड का प्रश्न है,

उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो आज सेलेक्ट कमेटी के सामने है, उसमें जो संशोधन किये जाने वाले है, उसके लिए जो सुझाव हैं, जो प्रपोजल्स है उन पर विचार हो रहा है और अगर उस सिलसिले मे कोई ठोस सुझाव हो तो ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी में उन पर विचार हो सकता है, आप जरूर उस मामले को वहां उठायें।

SHRI M. R. VENKATARAMAN (Tamil Nadu) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I was disappointed to hear the hon. Minister deal with the matters substantially only as a law and order problem. It is true that the culprits who have been responsible for this heinous crime should be brought to books and be properly punished. I am in complete agreement with my esteemed friends who have passed for such a punishment of those who are responsible for this tragedy. But then as the speaker before me, Mr. Chaudhary observed that it is a fact that the incident like that in Purnea has come to our light but there are thousands of such other incidents which do not come to our notice—it is still going on. I only wish to recall and bring to the notice of the Government and to this House the tragedy which took place on the eve of Christmas in the year 1968 in a village called Keezha Venmani in Tanjore District, Tamil Nadu, where 44 Harijan women and children and one or two males were locked up in a hut. Petrol was poured on the hut. It was set on fire and to add to that, when they tried to escape, they were pushed with bamboo poles into fire and that horror of the whole thing shook us all. But then that too was a result of a deliberate action on the part of landlords. It is not necessary for me to elaborate a point which has already been made by Mr. Gorary and other friends that there seems to be a conspiracy, how these wagons could came and all that. All these things are happening but my whole point is only this that it is not merely a question of law and order, there are still today places in Tamil Nadu, where in villages a Harijan cannot walk with his chappals on in the streets where the landlords live. There are places where no Harijan can talk to a landlord with his upper cloth on, he has to tie round on his waist to show proper respect. Now my point is that the landlords are able to do it because of the large tracts of land in their possession.

It is not a question of caste only. It is a question of landlords and the big landlordism. This is the lesson which such incidents bring home to us and specially to the Government which is incharge of the situation. It is not a question of trying to balance powers between the Central and the State Government. Whether it is the Central Government or it is the State Government, the question here is what are you going to do about the abolition of the landlordism in this country. Time and again, Chief Ministers have been called to Conferences and there was a recent Conference also, but it ended as usual with a Committee being formed to investigate into the question of what sort of land reforms should be introduced. I say, this point must go home with the Government in addition to whatever steps are being taken for the apprehension and punishment of culprits in this case. The point must go home to the Government that they cannot delay abolition of landlordism by a single day hereafter. There is no question of trying to balance the powers between the Centre and the State. It is enough to say that the well-to-do people with land, power and money are responsible for doing all this. When are the curbs going to be put on them so that they are not in a position to do so? I am talking of the big landlordism which is responsible for such crimes as this.

It is not just casual; not only that but I go further and say that there is softness in dealing with this. It is all right for the hon. Minister to come to day and say this is not a party question. He is quite right in saying that this is a larger question but to my mind it is not in that way only a law and order question. It is a national question of landlordism being abolished and in that sense we are interested in it as a national issue and the sooner that is attended to in that way the sooner will such incidents cease to happen in this country. Therefore I even charge the Government with being dilatory in this matter, with being pro-landlords in this matter and that enables the landlord elements to behave with impunity and kill hundreds of people wantonly.

SHRI K. C. PANT : Sir, I am sorry that I gave the impression to Shri

[Shri K. C. Pant]

Venkataraman that I looked at this purely as a law and order problem. In reply to an earlier question and even earlier than that I had made it very clear that this is not just a law and order problem. This incident of course is a law and order incident but there are deeper causes for this problem. Earlier on in the course of questions and answers I thought those has already been brought out. He referred to certain instances; I had also referred in my answer to the need to change basic attitudes and the effort required by all sections of this House and outside to see that whatever really we intend to achieve is in fact achieved and that is what we are committed to. Now he has talked of my reply which seeks to balance the powers of the Centre and the States. Sir, it is a fact that one has to operate within the constitution and if I understood his suggestion it was more or less to transfer land from the States to the Centre so that we can effect land reforms in all the areas from the Centre. That is the logic of his argument and if this is the extent to which he wants to go and I would certainly consider it if he would let me know that this is his view. Otherwise I have to operate within the limits of the Constitution.

SHRI CHITTA BASU : Yes, he as...

SHRI K. C. PANT : I do not know why Mr. Chitta Basu is answering for him. He is capable of answering himself.

Sir, on the question of softness in Delhi or being pro-landlords, may I remind Shri Venkataraman, whether it is the CPI-dominated Government in Bihar or whether it is the CPM-dominated Government in West Bengal..

SHRI M. R. VENKATARAMAN : The Government that was.

SHRI K C. PANT : . . under President's Rule we did more than the CPM-dominated Government could do in months of existence in Bengal in the matter of land reforms.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra-Pradesh) : I am sure the Government shares the anxiety of parliament and the country regarding the brutalities and inhuman acts like these.

Every time it is a *post mortem*. I know the constitutional and legal difficulties. I would urge upon the hon. Minister to discuss this matter in the Zonal Councils, discuss it with the Chief Ministers and find out some remedy so that the Government of India may have some hold and see that in the case of Harijans or Backward Classes such injustice and brutalities are put an end to for ever. I would like the Government to give some serious thought to this question and see that these things are not repeated in future.

SHRI K. C. PANT : Sir, as I said earlier in reply to Shri Goray, any suggestions which Hon. Members have welcome and any suggestions that made in this regard and coming from them will certainly receeive consideration. If they can take it up with the other opposition parties and a consensus can be evolved, we will certainly consider those suggestions in all sincerity. May I just point out to my respected friend, Mr. Akbar Ali Khan, that so far as preventing such incidents goes, from the narrower law and order point of view the police are with the States and they do have a certain responsibility ? The States are large administrative machines and they are not negligible by any means. They do shoulder heavy responsibilities and let us not create an impression that we think that the States are incapable of looking after these things. Consistent with that I would welcome any concerte suggestions that may emanate from any quarter in this regard. I share this concern of the House.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL ACCOUNTS (1969-70) OF THE BOMBAY PORT TRUST AND OTHER PAPERS

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT/संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI OM MEHTA) : Sir I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Annual Accounts of the Bombay Port Trust for the year